प्रेस विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सुझाव आमंत्रित

देहरादून, उत्तराखण्ड, 20.07.2026। देवभूमि उत्तराखण्ड में संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान-परम्परा तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक महत्त्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल करते हुए उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। यह आयोग संस्कृत के समग्र विकास , संस्थागत सुदृढ़ीकरण तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा।

संस्कृत शिक्षा सचिव श्री दीपक कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड ने 7 जनवरी, 2010 को संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान कर देश में एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह निर्णय केवल एक भाषाई पहल नहीं , बल्कि भारत की सनातन ज्ञान -परम्परा, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण का सशक्त संकल्प था।

संस्कृत शिक्षा सचिव श्री दीपक कुमार ने आगे कहा कि 1 दिसम्बर, 2025 को हरिद्वार स्थित उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संस्कृत के संरक्षण ,

संवर्धन, प्रचार-प्रसार तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक उच्चस्तरीय उत्तराखण्ड संस्कृत आयोग के गठन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया था। मुख्यमंत्री की इसी दूरदर्शी परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा 15 जुलाई , 2026 को देहरादून स्थित सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

संस्कृत शिक्षा सचिव श्री दीपक कुमार ने बताया कि इस महत्त्वपूर्ण पहल को व्यापक, समावेशी एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के लिए अब देशभर के संस्कृत विद्वानों , आचार्यों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, गुरुकुलों, संस्कृत संस्थानों, भारतीय ज्ञान-परम्परा के विशेषज्ञों , सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों तथा संस्कृत-प्रेमी नागरिकों से उनके बहुमूल्य सुझाव एवं अनुशंसाएँ ई-मेल के माध्यम से भी आमंत्रित की गई हैं।

संस्कृत शिक्षा सचिव श्री दीपक कुमार ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थान अपने सुझाव 10 अगस्त, 2026 तक ई-मेल vc@usvv.ac.in अथवा registrar@usvv.ac.in **पर प्रेषित कर सकते हैं।** प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाएगा तथा उपयुक्त सुझावों को आयोग की संरचना एवं कार्ययोजना में यथासंभव सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि प्राप्त सुझाव आयोग की संरचना , अधिकारों, कार्यक्षेत्र, नीति-निर्माण तथा भावी कार्ययोजना के

निर्धारण में महत्त्वपूर्ण आधार सिद्ध होंगे। उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य ऐसा सशक्त एवं प्रभावी आयोग स्थापित करना है, जो संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन के साथ -साथ उसे समकालीन आवश्यकताओं एवं भावी चुनौतियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान कर सके। प्रस्तावित आयोग के माध्यम से संस्कृत शिक्षा , उच्चस्तरीय शोध , पाण्डुलिपि संरक्षण एवं डिजिटलीकरण , भारतीय ज्ञान प्रणाली , वैदिक एवं शास्त्रीय अध्ययन , संस्कृत-आधारित कौशल एवं रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों , प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में संस्कृत के उपयोग , कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल माध्यमों में संस्कृत की संभावनाओं तथा जन -जन तक संस्कृत के प्रभावी प्रसार के लिए दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्ययोजनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

PRESS RELEASE

National-Level Suggestions Invited for the Constitution of the Uttarakhand Sanskrit Commission

Dehradun, Uttarakhand, 20 July 2026: In a significant and visionary initiative aimed at the preservation, promotion, and effective implementation of the Sanskrit language, Indian Knowledge System, and India's rich cultural heritage in Devbhoomi Uttarakhand, the Government of Uttarakhand has initiated the process for the constitution of the Uttarakhand Sanskrit Commission. The proposed Commission is expected to become a historic milestone in ensuring the holistic development of Sanskrit, strengthening institutional mechanisms, and expanding its meaningful application across diverse sectors of society.

The Secretary, Sanskrit Education, Shri Deepak Kumar, stated that Uttarakhand had set a unique national example by declaring Sanskrit as the Second Official Language of the State on 7 January 2010. This landmark decision was not merely a linguistic initiative but a firm commitment towards preserving India's timeless knowledge tradition, cultural consciousness, and spiritual heritage.

Shri Deepak Kumar further informed that during the International Sanskrit Conference organised by Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar, on 1 December 2025, the Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami, had strongly emphasized the need for establishing a high-level Uttarakhand Sanskrit Commission to ensure the preservation, promotion, dissemination, and effective implementation of Sanskrit. In pursuance of the Hon'ble Chief Minister's visionary initiative, the process for constituting the Commission was taken forward, culminating in a high-level meeting held at the State Secretariat, Dehradun, on 15 July 2026.

The Secretary further stated that, with a view to making this important initiative comprehensive, inclusive, and national in character, valuable suggestions and recommendations are now being invited through email from Sanskrit scholars, Acharyas, teachers, researchers, universities, colleges, Gurukuls, Sanskrit institutions, experts in the Indian Knowledge System, social and cultural organisations, and all citizens devoted to the promotion of Sanskrit across the country.

Interested individuals and institutions are invited to submit their valuable suggestions by 10 August 2026 via email at vc@usvv.ac.in or registrar@usvv.ac.in.All suggestions received will be examined with due seriousness, and suitable recommendations will, as far as possible, be incorporated into the structure and functional framework of the proposed Commission.

Shri Deepak Kumar further stated that the suggestions received will serve as an important foundation for determining the Commission's organisational structure, powers, jurisdiction, policy framework, and future roadmap. The Government of Uttarakhand aims to establish a robust and effective Commission that will not only safeguard and promote Sanskrit but also provide it with renewed relevance in accordance with contemporary needs and emerging global challenges.

The proposed Commission envisions formulating long-term policies and strategic action plans for the promotion of Sanskrit education, advanced research, preservation and digitisation of manuscripts, the Indian Knowledge System, Vedic and classical studies, Sanskrit-based skill development and employment-oriented programmes, the use of Sanskrit in governance and technology, the application of Sanskrit in Artificial Intelligence and digital platforms, and the effective dissemination of Sanskrit among the wider public.